CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

निकट भविष्य में दूध खरीद की कीमतें स्थिर/कम रहने की संभावना है

हाल के उद्योग विश्लेषणों से संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में दूध खरीद की कीमतें स्थिर रहने या यहां तक कि मामूली कमी आने की उम्मीद है। अगस्त 2023 में थोक दूध की कीमतों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई है, जो डेयरी बाजार के लचीलेपन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण भारत में दूध की कीमत मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट देखी जा रही है, कुछ मासिक उतार-चढ़ाव के बावजूद, दिसंबर 2022 में दरें 12.8% से गिरकर अगस्त 2023 में 9.6% हो गईं। महत्वपूर्ण रूप से, 2023 के अंत तक दूध खरीद की कीमतें स्थिर या थोड़ी कम रहने की उम्मीद है। यह आशावाद एक मजबूत फ्लश सीज़न, सामान्य मानसून पैटर्न, ढेलेदार त्वचा रोगों के कम होते प्रभाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्थिरीकरण से मजबूत हुआ है।

विश्लेषकों ने वित्तीय वर्ष 2024 के उत्तरार्ध और वित्तीय वर्ष 2025 में डेयरी क्षेत्र में चक्रीय सुधार की भविष्यवाणी करते हुए एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है। यह दृष्टिकोण उद्योग के मजबूत रिटर्न अनुपात द्वारा समर्थित है, जो लगातार पूंजी की लागत और क्षमता से अधिक है वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में मार्जिन रिकवरी के लिए।

केरल ने 67 वर्षों के बाद पशुपालन और डेयरी विकास विभागों को स्वतंत्र दर्जा दिया

पशुपालन और डेयरी विभाग
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

एक अभूतपूर्व कदम में, केरल राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर पशुपालन और डेयरी विकास विभागों को स्वतंत्र दर्जा प्रदान कर दिया है, जिससे कृषि विभाग के साथ उनका 67 साल पुराना संबंध समाप्त हो गया है। यह परिवर्तन इन विभागों द्वारा अपने कृषि परिदृश्य में निभाई जाने वाली विशिष्ट भूमिकाओं के प्रति राज्य की मान्यता को दर्शाता है।

1956 में राज्य के गठन के बाद से, ये विभाग कृषि के अंतर्गत संचालित होते थे। हालाँकि, अब पशुपालन विभाग के अधीन कई पशु चिकित्सालयों, मवेशी विकास परियोजनाओं और आईसीडीपी उप-केंद्रों के साथ, स्वतंत्रता की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है।

पहले, आधिकारिक रिकॉर्ड इन संस्थाओं को उनकी फाइलों, पत्रों और आदेशों में 'कृषि' की अनुपस्थिति के बावजूद 'कृषि (डेयरी विकास)' और 'कृषि (पशुपालन)' के रूप में संदर्भित करते थे।

यूपी ने स्वदेशी गाय की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए "मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना" शुरू की

इस पहल के तहत, अन्य राज्यों से साहीवाल, थारपारकर, गिर और संकर नस्ल की गाय खरीदने वाले गाय चरवाहों को परिवहन, पारगमन बीमा और पशु बीमा खर्चों को कवर करने वाली सब्सिडी मिलेगी। वे अधिकतम दो स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर अपने कुल खर्च का 40% तक की सब्सिडी से लाभ उठा सकते हैं, जिसकी सीमा ₹80,000 है। यह योजना शुरू में राज्यव्यापी विस्तार की योजना के साथ 18 संभागीय मुख्यालय जिलों में शुरू होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन के हिस्से के रूप में "मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना" का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य गाय पालकों की आय बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और स्वदेशी गाय की नस्लों का संरक्षण करना है। कार्यक्रम के पात्रता मानदंड, सब्सिडी बेंचमार्क, उद्देश्य और ब्लूप्रिंट को हाल के एक निर्देश में रेखांकित किया गया है।

गांठदार त्वचा रोग ने नासिक, महाराष्ट्र को प्रभावित किया; पशु व्यापार पर प्रतिबंध

गांठदार त्वचा रोग की विशेषता बुखार और गांठ जैसी दिखने वाली त्वचा की गांठें होती हैं, जिससे दूध उत्पादन में अस्थायी कमी आती है, बैलों में संभावित बांझपन, छिपाने की क्षति और, कुछ मामलों में, मृत्यु हो जाती है।

महाराष्ट्र के नासिक जिले को गोजातीय पशुओं में गांठदार त्वचा रोग के लिए प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिससे मवेशियों की खरीद और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह वायरल बीमारी जिले के 15 तालुकाओं में से 12 में मवेशियों में फैल गई है। कलेक्टर जलज शर्मा ने महामारी पर नियंत्रण के लिए निवारक टीकाकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रकोप को रोकने के लिए, जिले ने गोजातीय पशुओं की खरीद, बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसे लागू करने के लिए पुलिस की सहायता मांगी गई है। गुजरात से सटे सीमावर्ती जिले नासिक को पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत एक प्रभावित क्षेत्र नामित किया गया है।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी मामले का पता चलने पर तुरंत निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और शव का उचित निपटान सुनिश्चित करें। हाल ही में, महाराष्ट्र के नांदेड़ को भी प्रभावित जिला घोषित किया गया था, जहां 3,600 से अधिक जानवर इस बीमारी से पीड़ित थे।

महानपुर, जम्मू में किसानों को समर्पित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई

पशु स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, जम्मू में पशुपालन विभाग की निदेशक डॉ. शुभ्रा शर्मा ने महानपुर ब्लॉक के किसानों को एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (एमवीयू) समर्पित की। समर्पण समारोह कठुआ की पंचायत मारा-पट्टी में हुआ और इसमें प्रमुख अधिकारियों और किसानों की एक बड़ी सभा ने भाग लिया।

इसके अलावा, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी), एकीकृत डेयरी विकास योजना (आईडीडीएस), एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (आईपीडीपी) सहित पशुपालन विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को सूचित करने के लिए समर्पण कार्यक्रम के साथ-साथ एक मेगा-जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया था। , राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और राष्ट्रीय पशुधन मिशन। विशेषज्ञों ने इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जाये इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी.

डॉ. शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि एमवीयू का प्रावधान आवश्यक पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे किसानों के दरवाजे तक पहुंचाने की एक अभूतपूर्व पहल है। एमवीयू एक पशु चिकित्सक, एक पैरा-वेट, और खेत जानवरों पर छोटी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के इलाज और संचालन के लिए आवश्यक दवाओं और उपकरणों के साथ काम करेगा। किसान टोल-फ्री नंबर '1962' पर कॉल करके इन सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।

डॉ. शर्मा ने स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मैट्रिस और एएचईएलपी जैसी स्व-रोजगार सृजन पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, राशन संतुलन और दूध रिकॉर्डिंग जैसी महत्वपूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे युवाओं और स्थानीय पशुधन मालिकों दोनों को लाभ होता है। .

जिला विकास परिषद कठुआ के अध्यक्ष कर्नल महान सिंह ने आशा व्यक्त की कि एमवीयू के लॉन्च से पशुधन उत्पादकता और पशुपालन क्षेत्र से जुड़े किसानों की आय के स्तर में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य पशुपालन अधिकारी कठुआ, डॉ. युगल किशोर, विस्तार अधिकारी डॉ. नदीम अहमद और कठुआ में पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

डेयरी फार्मिंग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना एक और उल्लेखनीय पहलू है। महिलाएं, शेखपोरा के एक डेयरी किसान की तरह, जो गायों की एक छोटी इकाई का प्रबंधन करती हैं, अपने घरों में योगदान दे रही हैं और पहचान अर्जित कर रही हैं।

मुंबई में भैंस के दूध की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ीं

1 सितंबर, 2023 से, मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (एमएमपीए) ने ताजा भैंस के दूध की थोक कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे यह 85 रुपये से बढ़कर 87 रुपये प्रति लीटर हो गई है। यह मूल्य समायोजन 28 फरवरी, 2024 तक प्रभावी रहेगा। पशु शेड मालिकों और थोक विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एमएमपीए को उम्मीद है कि खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं से 5-7 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त शुल्क लेंगे, जिससे भैंस के दूध की बाजार दर 92-94 रुपये प्रति लीटर हो सकती है।

मूल्य वृद्धि के बावजूद, भैंस का दूध एक समर्पित उपभोक्ता आधार बनाए रखता है, खासकर उन लोगों के बीच जो गाढ़ा दही बनाने के लिए इसकी ताजगी पसंद करते हैं, जो मुंबई में इसकी लोकप्रियता की पुष्टि करता है।

एसोसिएशन के एक कार्यकारी सदस्य सी के सिंह ने बताया कि एमएमपीए दूध की दरों को संशोधित करने के लिए अर्धवार्षिक बैठकें आयोजित करता है, लेकिन लागत तेजी से बढ़ रही है। मार्च में, चारे की बढ़ती लागत, पशु चारे की कीमतों में 20% की वृद्धि और दुधारू पशुओं के बढ़ते खर्च के कारण दूध की कीमतें 5 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये से 85 रुपये प्रति लीटर कर दी गईं। सिंह ने देश भर में दूध किसानों के बीच व्यापक संकट को स्वीकार किया।

डेयरी फार्मों, गौशालाओं के लिए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी जरूरी

डेयरी फार्मों और गौशालाओं के मालिकों को संचालन के लिए इसकी सहमति लेने का निर्देश देते हुए, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने उनसे आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने और संशोधित पर्यावरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने या जुर्माना भुगतने को कहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश गौशालाएं और डेयरियां गोबर और अपशिष्ट जल को नालियों में बहाती रहती हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है।

नये दिशानिर्देश

- नए डेयरी फार्म और गौशालाएं शहर/गांव की सीमाओं के बाहर स्थित होनी चाहिए
- ये आवासीय इकाइयों से कम से कम 200 मीटर और अस्पतालों और स्कूलों से 500 मीटर दूर होने चाहिए
- नए डेयरी फार्म और गौशालाएं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में स्थित नहीं होनी चाहिए

पीपीसीबी ने डेयरी फार्मों और गौशालाओं के मालिकों से कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करना और इकाई स्थापित करने के लिए सहमति लेना अनिवार्य है।

सहमति में यह वचन देना शामिल है कि डेयरियां और फार्म अपशिष्ट जल को सीवरों में छोड़ने से पहले उसका उपचार करेंगे और गोजातीय गोबर डालना बंद कर देंगे। पीपीसीबी की मंजूरी तभी मिलेगी जब इकाइयां नियमित अंतराल पर शेडों से गोबर इकट्ठा करेंगी।

“वर्तमान में, अधिकांश डेयरियाँ मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं और हवा और पानी दोनों को प्रदूषित कर रही हैं। इसे रोकना होगा या एनजीटी के आदेश के मुताबिक डिफॉल्टरों से पर्यावरण मुआवजा वसूला जाएगा। वर्तमान में, अधिकांश फार्म बिना किसी मानदंड का पालन किए चल रहे हैं, ”पीपीसीबी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा।

रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से सीईडीएसआई ने बीदर, कर्नाटक में डेयरी किसानों और विस्तार श्रमिकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया

सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (सीईडीएसआई) ने रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से कर्नाटक के बीदर में डेयरी किसानों और विस्तार श्रमिकों के लिए एक व्यापक तीन दिवसीय प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। क्षेत्रीय भाषा में आयोजित प्रशिक्षण सत्रों में साइलेज बनाने और जातीय-पशु चिकित्सा प्रथाओं पर व्यावहारिक प्रदर्शन शामिल थे, जो प्रशिक्षण के अंतिम दिन मूल्यवान व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते थे। प्रशिक्षण क्षेत्रीय भाषा में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य प्रतिभागियों की दक्षता को बढ़ाना था। यह गहन कार्यक्रम 27 अगस्त से 29 अगस्त तक चला और इसमें कुल 30 उम्मीदवारों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से सेडसी का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रकाशम जिले, एपी में डेयरी किसानों को सशक्त बनाता है

सेडसी ने रिलायंस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में हाल ही में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र में डेयरी किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ाना था। प्रशिक्षण के तीसरे दिन को प्रतिभागियों को साइलेज बनाने और जातीय-पशु चिकित्सा प्रथाओं में व्यावहारिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रदर्शनों में शामिल होने का अवसर मिला, जिससे उन्हें मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और डेयरी फार्मिंग और विस्तार कार्य की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने में मदद मिली। सेडसी और रिलायंस फाउंडेशन के बीच सहयोगात्मक प्रयास ने स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने और टिकाऊ डेयरी प्रथाओं को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। डेयरी किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं के विकास में निवेश करके, वे प्रकाशम जिले में डेयरी क्षेत्र के विकास में योगदान करते हैं, जिससे अंततः किसानों और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होता है।

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

CEDSI

Centre of Excellence for Dairy Skills in India

Join Our Membership Drive and Get Benefits of

- Platform to interact with other members in the sector
- Networking opportunities with corporate leaders and government authorities
- Special costs of training in Skill India Certified Programmes
- Access to our Journal and Publications
- Expert advice in day-to-day operations and management of livestock /farm productions
- Free registration on the job portal and regular updates on job vacancies in the sector
- Recognize your organization with CEDSI Yearly Awards and Recognition
- Chance to reach across the board through advertising in our press releases, news and articles
- Consultative and advisory services to help members
- Consulting and advisory services to help members
- Periodic e-newsletter for the latest news, govt. announcement and schemes in dairy sectors
- Updates on training programs of CEDSI and access to the training calendar

Who Can Become a Member -

Corporates/ Cooperatives

NGO's/CSR Foundations

Dairy Farmers

Students

Professional

www.cedsi.in

@cedsi_india

CEDSI : रविविंग स्किल्स एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड

किसानों/छात्रों/उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डेयरी किसान / उद्यमी
- डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
- डेयरी कार्यकर्ता
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
- पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
- पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक
- बछड़ा पालन
- कृषि उपकरण तकनीशियन
- डेयरी फार्म अर्थशास्त्र और प्रबंधन
- उद्योग संरेखित प्रमाणन कार्यक्रम (बेरोजगार युवा और छात्र)

एफपीओ उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उत्पाद प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर एफपीओ सदस्य अभिविन्यास।
- एफपीओ मार्केट लिंकेज
- एफपीओ शासन
- एफपीओ लेखा

डेयरी कॉरपोरेट्स और सहकारी समितियों के लिए प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- चिलिंग प्लांट तकनीशियन
- बल्क मिल्क कूलर ऑपरेटर
- ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रह केन्द्र पर्यवेक्षक
- दूध परीक्षक
- ग्रीन हाउस गैसों का शमन
- दूध की गुणवत्ता आश्वासन
- मिल्क डिलीवरी बॉय
- दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक
- डेयरी उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन
- चारा और चारा प्रबंधन
- स्वच्छ दूध उत्पादन
- निर्णय समर्थन प्रणाली / डेटा विश्लेषिकी

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया